



rcues

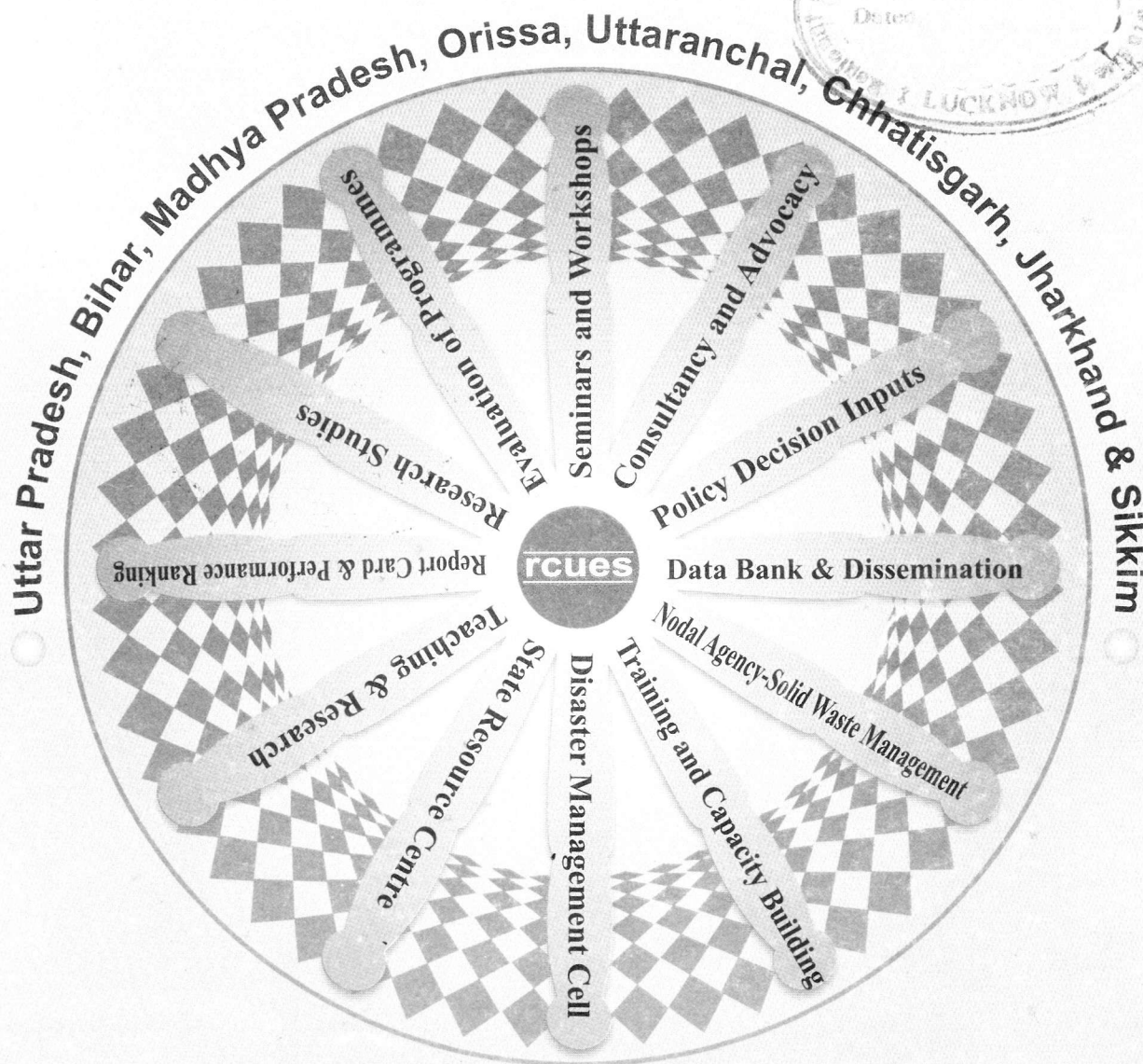
# RCUES NEWSLETTER

(A Quarterly Publication)

VOL. 2

January-March, 2006

No.1



## INSIDE

- Academic Activities (January to March, 2006)
- Academic Calendar (April 2006- March 2007)
- Faculty News

## Chief Editor

Prof. Nishith Rai (Director)

## Editor

Dr. Richa Varmani (Joint Director)

Editorial Asstt.

Dr. R.K. Trivedi (Asstt. Librarian)

## Regional Centre for Urban & Environmental Studies

(Established by the Ministry of Urban Development, Govt. of India in 1968)  
Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow- 226 007 (INDIA)



RCUES PREMISES



TRAINEES HOSTEL



CONFERENCE ROOM



LIBRARY



MEETING ROOM

*Please mail your correspondence to :*

**Prof. Nishith Rai**

Director

Regional Centre For Urban & Environmental Studies

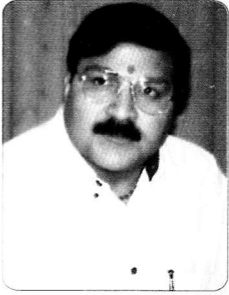
(Established by Ministry of Urban Development, Government of India)

Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow - 226 007 (INDIA)

Tel. : (0522) 2740165, 2740108, Fax : (0522) 2740165

e-mail : [nkrai@hotmail.com](mailto:nkrai@hotmail.com) ● [director@rcueslko.org](mailto:director@rcueslko.org) ● Website [rcueslko.org](http://rcueslko.org)





## From the Chief Editor's Desk



प्रो. निशीथ राय

प्रिय पाठको,

भारतवर्ष के स्थानीय स्वायत्तशासन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 74वें संविधान संशोधन द्वारा उठाया गया। इसके द्वारा स्थानीय निकायों को विकेन्द्रीकरण के पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये। परिणामस्वरूप, इस दृष्टिकोण से अनेक अधिनियम पारित किये गये ताकि स्थानीय निकायों के लोकतांत्रिक स्वरूप तथा उनके अधिकारों और कार्यों का और अधिक विस्तार सम्भव हो सके। कार्यों की सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय स्थानीय निकायों का कार्य नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराने के परम्परागत कार्यों तक ही सीमित नहीं है, अपितु संविधान ने इन निकायों की गरीबी उन्मूलन, आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक विकास में भी सक्रिय भूमिका निर्धारित की है।

बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण जो मुख्य चुनौतियां सामने आयी हैं, उनमें मलिन बस्तियों की बढ़ती हुई जनसंख्या, मकानों की अत्यधिक कमी, पीने हेतु स्वच्छ पानी की आपूर्ति में कमी, पर्यावरणीय खतरे जैसे— हवा, जल तथा ध्वनि प्रदूषण, कूड़ा—करकट, भूमि पर दबाव, अवैध कब्जे, अव्यवस्थित नगरीय वृद्धि आदि प्रमुख हैं। हमें इन चुनौतियों का डटकर तथा युक्तिपूर्ण ढंग से सामना करना होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में मा०प्रधानमंत्री, डा०मनमोहन सिंह ने 3 दिसम्बर, 2005 को 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन' के नाम से एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना देश को समर्पित की, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 नगर निगमों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एवं मेरठ) तथा एक नगर पालिका परिषद् (मथुरा) को चयनित किया गया है। इस योजना के द्वारा स्थानीय निकायों को तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को, विशेष रूप से बड़े शहरों में मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे— सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, सफाई, नाली, जल—कल निस्तारण, मार्ग प्रकाश, सड़कें, परिवहन व्यवस्था आदि की सुचारु व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को अपने संसाधनों के आधार को विस्तृत एवं सघन बनाना होगा। साथ ही अपनी संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा तथा उनकी अधिकार सम्पन्नता को सुनिश्चित करना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जा चुके हैं एवं रीजनल सेंटर भी जे०एन०एन०यू०आर०एम०हेतु 'स्टेट रिसोर्स सेंटर' एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 'नोडल एजेन्सी' के रूप में अपनी भूमिका से सफलतापूर्वक योजना के कुशल प्रबंधन द्वारा सक्रिय योगदान कर रहा है।

सभी स्थानीय निकायों से इस 'न्यूज लेटर' के माध्यम से अनुरोध है कि वे अपनी संस्था में नवाचार प्रयोगों से रीजनल सेंटर को अवगत कराते रहें, ताकि उनके द्वारा किये जा रहे नवीनतम कार्यों से अन्य संस्थायें भी प्रेरित हो सकें।

हम आशा करते हैं कि पूर्व की भाँति इस कार्य में आपका सहयोग सदैव प्राप्त होता रहेगा। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

**निशीथ राय**

निशीथ राय  
निदेशक / मुख्य सम्पादक



Dr. Richa Varmani

## *From the Editor's Desk*



**rcues**

### ***Esteemed Readers,***

*As we all know, cities have strongly emerged as the prime engines of the Indian economy and generators of national wealth. Looking at the past almost sixty years of India since Independence, it is evident that its future is inescapably urban. It is, therefore, high time that the cities deliver a quality of life that would enable them to become national assets and engines of economic growth. In fact, India's urban issues with all their related challenges and opportunities demand their firm place on the national agenda.*

*Several key issues of good urban governance stand out in the Indian context. These are decentralization, integration of the poor and marginalised, environmental sustainability, mobilisation of municipal finance, transparency and civic engagement, better municipal management and capacity building. These issues are inextricably linked to each other and cannot be seen in isolation.*

*The Government of India has recently taken certain welcome steps to strengthen urban infrastructure and meet the urban challenges of today. Envisioning a city, setting its priorities, promoting civil society participation and norms of good urban governance, raising resources - all form part of the task of municipal management. However, focused Action Plans which should be locally developed consultatively with full participation of all the stake holders are the need of the hour.*

*The Regional Centre, Lucknow, has been actively involved in expanding its activities since the past few years in order to keep pace with the challenging task of providing integrated approach through its multifarious academic activities.*

*Once again, we invite news about policies and initiatives that you may want to share with others in the same field. We look forward to your valuable suggestions in our future endeavours.*

*With Best Regards.*

*Richa Varmani*

**Richa Varmani**

Joint Director / Editor



# RCUES NEWS

## Academic Activities (January to March, 2006)

### ➤ Orientation Workshops

**JNNURM, UIDSSMT**

**& IHSDP**

**Venue : Lucknow**

**Dates : January 18, 19 and 20, 2006**

In fulfillment of the desire of the State Government of Uttar Pradesh, the Regional Centre oriented the Executive Officers of all the towns having a population of more than 50,000 on the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT) and Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP).

These one-day Orientation Workshops were organised on January 18, January 19 and on January 20, 2006 on JNNURM, UIDSSMT IHSDP with the following main objectives :

- ❖ to highlight the main provisions of JNNURM, UIDSSMT and IHSDP
- ❖ to emphasize on the need of developing small and medium towns  
to discuss the importance, need and techniques for preparing CDPs and DPRs
- ❖ to identify the areas for PPP in the provision of urban services etc.

The programmes were attended by Municipal Commissioners/Additional Municipal Commissioners of all the Nagar Nigams and Executive Officers of all the Nagar Palika Parishads having population of 50,000 or above. About 62 officers each attended on 18<sup>th</sup> January and on 19<sup>th</sup> January and 48 on 20<sup>th</sup> January 2006. In all, 172 officers were oriented.

The faculty for these programmes was drawn from the core faculty of the Centre and representatives of State Government, SUDA and Directorate of Urban Local Bodies who also enriched the deliberations. The guest faculty included Sri S.P. Singh, Special Secretary, Urban Development, U.P.; Sri Diwakar Tripathi, Director, SUDA and Smt. Alka Srivastava, Director of Urban Local Bodies U.P.

### ➤ ओरियन्टेशन कार्यशाला

**जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.**

**एम.टी. और आई.एच.एस.डी.पी.**

**स्थान : लखनऊ**

**तिथि : जनवरी 18, 19 तथा 20, 2006**

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउंस (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) तथा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आई.एच.एस.डी.पी.) योजनाओं की जानकारी उत्तर प्रदेश के उन नगरीय निकायों जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है, के अधिकारियों को दी गई। यह तीन कार्यशालायें उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छानुसार आयोजित की गई।

यह कार्यशालायें क्रमशः जनवरी 18, 19, एवं 20, 2006 को तीनों योजनाओं को आच्छादित करते हुए आयोजित की गई। कार्यशालाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे :

- ❖ जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. योजनाओं के मुख्य तथ्यों से अवगत करवाना
- ❖ छोटे एवं मझोले कस्बों के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालना
- ❖ सिटी डेवलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.) एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को तैयार करने की तकनीकों पर विचार-विमर्श करना, तथा
- ❖ नगरीय सेवाओं को प्रदान करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के क्षेत्रों को चिन्हित करना।

कार्यशाला में नगर निगमों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों ने भाग लिया। कुल 172 अधिकारियों ने कार्यशालाओं में प्रतिभागिता दर्ज करायी, जिसमें जनवरी 18 तथा 19 को प्रत्येक दिन 62 अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि जनवरी, 20 2006 को 48 अधिकारियों ने भाग लिया।

उपरोक्त कार्यक्रम हेतु सेन्टर की कोर फैकल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार, सूडा एवं स्थानीय निकाय निदेशालय के प्रतिनिधियों ने भी अपना वक्तव्य दिया। अतिथि वक्ताओं में प्रमुखतः श्री एस0पी0 सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक सूडा एवं श्रीमती अलका श्रीवास्तव, निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे।

All these Workshops were coordinated by Dr. U.B. Singh, Joint Director in active association with Dr. Rajeev Narayan, Deputy Director.

### ➤ Training Programme

#### **'Planning for Healthy City'**

Venue : Lucknow

Dates : January 23 to 25, 2006

Various countries, including India, have formulated policies and programmes to deal with environmental and health-related problems, since they have been witnessing population concentration and growth due to migration from rural areas. Keeping the above issues in mind, the Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Lucknow organised a three days' training programme on Planning for Healthy City, the first of its kind, from January 23-25, 2006 for the municipal officials of the State of Uttar Pradesh.

The main objectives of the training programme were

- ❖ to sensitize the officials towards integrated health, sanitation and urban waste management in cities and the proper handling of bio-medical wastes and
- ❖ to discuss the various aspects of urban environment management, and control of communicable diseases.

There was a Panel Discussion on "Planning for Healthy City: Some Important Issues and Suggestions" in which the participants interacted with the expert panelists. The Panel Discussion was jointly presided by Sri S.A.T. Rizvi, senior bureaucrat and Chairman, IIIrd State Finance Commission, Government of Uttar Pradesh and Sri S.P. Singh, Special Secretary, Urban Development Department, U.P.

The programme was attended by 20 senior officers, who included Assistant Municipal Commissioners of Nagar Nigams and Executive Officers of various Nagar Palika Parishads of Uttar Pradesh.

All the participants were enthusiastic about learning the various issues relating to general health of the citizens, especially the details of management of hospital waste and communicable diseases. They even suggested that study tours should be conducted to foreign countries and other states within the country.

The training programme was coordinated and directed by Dr. Richa Varmani, Joint Director and Dr. Anjali Mishra, Deputy Director who was the Co-Course Director.

उपरोक्त तीनों कार्यशालायें डा० यू०बी० सिंह, संयुक्त निदेशक, रीजनल सेंटर ने डा० राजीव नारायण, उप निदेशक के सहयोग से आयोजित की।

### ➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम

#### **'प्लानिंग फार हेल्दी सिटी'**

स्थान : लखनऊ

तिथि : जनवरी 23 से 25, 2006

अन्य देशों की भाँति, भारतवर्ष में भी बढ़ती जनसंख्या तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से निरन्तर नागरिकों का पलायन हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रीजनल सेंटर, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश राज्य के म्युनिसिपल अधिकारियों हेतु एक त्रि-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 'प्लानिंग फार हेल्दी सिटी' विषय पर दिनांक जनवरी 23 से 25, 2006 आयोजित किया।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे :-

- ❖ शहरों में स्वास्थ्य, सफाई एवं नगरीय कूड़ा प्रबन्धन एवं बायोमेडिकल वेस्ट की उचित व्यवस्था के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराना तथा
- ❖ नगरीय पर्यावरण प्रबन्धन एवं संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हेतु विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना।

कार्यक्रम के दौरान एक पैनल परिचर्चा 'स्वस्थ शहर का नियोजन : कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सुझाव' विषय पर आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया। परिचर्चा की अध्यक्षता श्री एस.ए.टी. रिजवी, अध्यक्ष, तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री एस०पी० सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

कार्यक्रम में 20 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी शामिल थे।

जनता के सामान्य स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, विशेषकर अस्पतालीय कचरा एवं संक्रामक रोगों के बारे में जानने हेतु सभी प्रतिभागी अत्यंत आतुर थे। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में एवं विदेशों में भी अध्ययन भ्रमण हेतु ले जाने के लिए सुझाव दिये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन डा० ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक तथा डा० अंजुली मिश्रा, उप निदेशक द्वारा किया गया।



## ✦ Workshops **Solid Waste Management**

Venue : Lucknow  
Dates : February 7, 2006 and  
February 9, 2006

Management of Municipal Solid Waste (MSW) resulting from rapid urbanization has become a serious concern for all because of poor resources and inadequacies of the existing systems. The issue of solid waste management has been given significant importance in both the newly launched schemes of JNNURM and UIDSSMT. The Twelfth Finance Commission has also given priority to solid waste management and has recommended spending of minimum 50% finance for solid waste management in class I towns. Hence, the Regional Centre organized two Workshops on this important issue.

The specific objectives were to familiarize the participants with the concept and principles of solid waste management and its environmental impact on land; methods of its disposal; to discuss the waste management options and best practices as well as the issues relating to preparation of DPRs in SWM.

The Workshops were based on lecture-cum-discussions. Enough time was devoted to discussion and problem solving. There was also a Panel Discussion on 'Solid Waste Management'.

The participants of the first Workshop were Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners, Nagar Swasthya Adhikaris and Engineers from Nagar Nigams, government officials from the Department of Urban Development and representatives of NGOs working in urban development and solid waste management. In all, there were about 40 participants in the Workshop.

The participants of the second workshop were Executive Officials from the department of Urban Development, and local bodies and representatives of NGOs working in solid waste management. There were about 30 participants in all.

The external faculty consisted of Shri. S.P. Singh Special Secretary, Urban Development, U.P.; Smt. Alka Srivastava, Director, Local Bodies; Shri Kedar Nath, Additional Director, Local Bodies, and Shri Anand Prakash, Environmental Engineer.

Shri S.P. Singh, Special Secretary, Urban Development, U.P. acquainted the participants with the commitment of the government towards solid waste management. Dr. U.B. Singh, Joint Director also delivered lectures.

The Workshops were directed by Dr. Rajeev Narayan, Deputy Director.

## ✦ कार्यशालायें **'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट'**

स्थान : लखनऊ  
तिथि : फरवरी 7, 2006 तथा  
फरवरी 9, 2006

बढ़ते हुए नगरीकरण के परिणामस्वरूप पालिका ठोस कूड़े का प्रबन्धन, वित्तीय स्रोतों में कमी एवं वर्तमान दोषपूर्ण नीतियों के कारण एक गम्भीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। अतः पर्यावरण, प्रदूषण एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए नगरीय कूड़े के उचित प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। नयी केन्द्रीय योजनायें, यथा जे. एन. एन. यू.आर.एम. एवं यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी. में भी ठोस कूड़े प्रबन्धन पर भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। बारहवें वित्त आयोग ने ठोस कूड़े प्रबन्धन को प्राथमिकता देते हुए संस्तुति की है कि प्रथम श्रेणी के नगरों में कम से कम 50 प्रतिशत धन इस कार्य हेतु व्यय किया जायेगा। रीजनल सेंटर ने भी इसके महत्व को दृष्टिगत करते हुए इस विषय पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया।

कार्यशालाओं का विशेष उद्देश्य प्रतिभागियों को ठोस कूड़ा प्रबन्धन की धारणा एवं सिद्धांतों से परिचित करवाना एवं भूमि पर पर्यावरणीय प्रभाव, निस्तारण के उपाय, कूड़ा प्रबन्धन के अन्य एवं सर्वोत्तम कार्यों से परिचित करवाना थे। ठोस कूड़ा प्रबन्धन के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के तरीकों पर भी विचार किया गया।

कार्यशाला व्याख्यान एवं परिचर्चा पर आधारित थी। अधिकतर समय विचार-विमर्श एवं समस्याओं के निराकरण में व्यतीत किया गया। कार्यशाला के दौरान 'ठोस कूड़ा प्रबन्धन' पर एक पैनल परिचर्चा का भी आयोजन किया गया।

प्रथम कार्यशाला में नगर निगमों से नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभियंता, नगर विकास विभाग के अधिकारी तथा गैर सरकार संस्थानों के प्रतिनिधिगण, जो कि नगरीय विकास एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन के कार्यों से सम्बद्ध हैं, सम्मिलित हुए। कार्यशाला में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दूसरी कार्यशाला में अधिशासी अधिकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में कुल 20 प्रतिभागी थे।

अतिथि वक्ताओं में श्री एस०पी० सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन; श्रीमती अलका श्रीवास्तव, निदेशक, स्थानीय निकाय; श्री केंदार नाथ, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय एवं श्री आनन्द प्रकाश, पर्यावरणीय अभियंता सम्मिलित थे।

श्री एस०पी० सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग ने प्रतिभागियों को ठोस कूड़ा प्रबन्धन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। डॉ. यू.बी. सिंह, संयुक्त निदेशक ने भी व्याख्यान दिये।

दोनों कार्यशालाओं का समन्वयन डॉ. राजीव नारायण, उप निदेशक द्वारा किया गया।

➤ **Workshops**  
**'Report Card System'**

Venue : Lucknow

Date : February 8, 2006 and  
February 10, 2006

Report Card system was introduced in the State of U.P. on a pilot basis under the UNDP assisted project on 'Capacity Development for Urban Governance.' This system is now to become a regular feature and the performance of the service providers would be ranked on this basis. Hence the Centre organized two Workshops of one-day duration each on February 8 and 10, 2006 to familiarize the Municipal Officers with the report card system.

The objectives of the programmes were to familiarize the participants with the concept of report card system, to discuss the need and importance as well as the planning strategy, process and method of the report card system. The questionnaire prepared for the report card system was also discussed.

The Workshops were lecture-cum-discussion based. Detailed presentations were made on various aspects of report card system and enough time was devoted to discussion and problem solving. There was also a Panel Discussion on 'Report Card System'.

The participants of the Workshops were Executive Officers of Class-I towns, government officials from Department of Urban Development and representatives of NGOs working in urban development and solid waste management. In all there were 28 participants.

Shri S.P.Singh, Special Secretary, Urban Development, U.P. urged the officials to change their mind set, in order to improve their working and to encourage citizen's participation. Dr. U.B. Singh, Joint Director also delivered lectures.

The Course was directed by Dr. Rajeev Narayan, Deputy Director.

➤ **Workshops on**  
**UIDSSMT & IHSDP**

Venue : Lucknow

Date : February 14, 2006  
and February 15, 2006

Two Workshops, each of one day duration on Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) and Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) were organized by the Regional Centre on February 14 & 15, 2006.

The main objectives of the Workshops were :

➤ **कार्यशालायें**  
**रिपोर्ट कार्ड सिस्टम**

स्थान : लखनऊ

तिथि : फरवरी 8 , 2006 तथा  
फरवरी 10, 2006

रिपोर्ट कार्ड सिस्टम पहली बार उत्तर प्रदेश में यू0एन0डी0पी0 सहायित परियोजना 'नगरीय प्रशासन हेतु क्षमता विकास' के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी। वर्तमान में सेवा प्रदाय संस्थाओं के मध्य उनकी कार्य क्षमता को श्रेणीपद करने हेतु यह एक निरन्तर चलने वाली योजना बन गई है। क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा उपरोक्त विषय पर दिनांक फरवरी, 8 तथा 10, 2006 को म्युनिसिपल अधिकारियों को रिपोर्ट कार्ड सिस्टम से अवगत कराने हेतु दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की आवश्यकता एवं महत्व से अवगत कराना था। साथ ही साथ, योजना पद्धति एवं रिपोर्ट कार्ड सिस्टम के तरीकों पर भी चर्चा की गई। रिपोर्ट कार्ड सिस्टम हेतु तैयार की गई प्रश्नावली पर भी परिचर्चा की गई।

कार्यशाला व्याख्यान एवं परिचर्चा पर आधारित थी। अधिकतर समय विचार-विमर्श एवं समस्याओं के निराकरण में व्यतीत किया गया। कार्यशाला के दौरान 'रिपोर्ट कार्ड सिस्टम' पर एक पैनल परिचर्चा का भी आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रतिभागी प्रथम श्रेणी के नगरों के अधिशासी अधिकारियों के अतिरिक्त नगर विकास विभाग के अधिकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि थे जो नगर विकास एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन के कार्यों से सम्बद्ध हैं। कुल 28 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

श्री एस0पी0सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अधिकारियों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपने कार्यों में सुधार ला सकें एवं नागरिकों की प्रतिभागिता बढ़ सकें। डी0 यू0 बी0 सिंह, संयुक्त निदेशक ने भी व्याख्यान दिये।

कार्यशालाओं का निदेशन डा0राजीव नारायण, उप निदेशक द्वारा किया गया।

➤ **कार्यशालायें**  
**यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0**  
**तथा आई0एच0एस0डी0पी0**

स्थान : लखनऊ

तिथि : फरवरी 14, 2006 तथा  
फरवरी 15, 2006

रीजनल सेंटर द्वारा दो कार्यशालायें प्रत्येक यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. पर दिनांक फरवरी 14 तथा 15, 2006 को आयोजित की गयीं। उनके प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् थे :



- ❖ to acquaint the District Officers with the need and importance of developing infrastructure in small and medium towns
- ❖ to enlighten them with the salient features of UIDSSMT and IHSDP
- ❖ To prepare the strategy for implementation of these schemes.

The participants included the District Magistrates, Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners, Executive officers, Planners, Engineers and other officials.

In all, 51 officers attended the Workshop on February 14, 2006 and 42 officers participated in the Workshop held on February 15, 2006.

The Workshops were inaugurated by Shri Mohd. Azam Khan, Hon'ble Minister for Urban Development, Urban Employment & Poverty Alleviation and Parliamentary Affairs, Government of Uttar Pradesh. In his inaugural address, the chief guest stressed on the integrated development of rural and urban areas. Sri R. Ramani, Chief Secretary to U.P. Government exhorted the officials for efficient and timely implementation of these schemes for getting benefits from central assistance.

A comprehensive and detailed presentation on UIDSSMT and IHSDP was presented by Dr. U.B. Singh, Joint Director. Sri S.P. Singh, Special Secretary to Government of U.P. in the Department of Urban Development presented the strategy adopted and reforms undertaken by the State Government. Sri Diwakar Tripathi, Director, SUDA presented the strategy for implementing IHSDP. Smt. Alka Srivastava, Director of Local Bodies deliberated on the need and importance of early preparation of DPRs under UIDSSMT.

Sri D.C. Mishra, Secretary to U.P. Government in the Department of Urban Development and Shri A.K. Srivastava, Secretary, Housing and Urban Planning also highlighted the reforms.

While welcoming the guests, Prof. Nishith Rai, Director, RCUES deliberated on the need and importance of organising the Workshops for District Magistrates.

The Workshops were coordinated by Dr. U.B. Singh, Joint Director, RCUES.

## ➤ Training Programme

### **Urban Local Bodies :**

#### **New Perspective**

Venue : Lucknow

Dates : February 22 to 24, 2006

With a view to familiarising the participants, mainly consisting of Executive Officers from Nagar Panchayats on the various administrative and related financial issues, the Regional Centre for Urban and Environmental

- ❖ छोटे एवं मझोले शहरों में अवस्थापना विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर जिलाधिकारियों को अवगत कराना
- ❖ यू.आई.डी.एस.एम.टी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के प्रमुख तथ्यों से उन्हें परिचित कराना, तथा
- ❖ उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यनीति तैयार करना।

कार्यशाला में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, नियोजक, अधिशासी अधिकारी, अभियंता एवं अन्य अधिकारीगण सम्मिलित हुए। फरवरी 14 को 51 अधिकारियों एवं फरवरी 15, 2006 को 42 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री मो०आजम खान, माननीय मंत्री, नगर विकास, शहरी रोजगार एवं संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के समेकित विकास पर जोर दिया। श्री आर० रमणी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्रीय सहायित उपरोक्त परियोजनाओं के कुशल एवं सामयिक क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला।

डा०यू०बी०सिंह, संयुक्त निदेशक ने यू.आई.डी.एस.एम.टी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। श्री एस०पी०सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत कार्य-नीति एवं सुधारात्मक कार्यों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक, सूडा ने आई.एच.एस.डी.पी. के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। श्रीमती अलका श्रीवास्तव, निदेशक, स्थानीय निकाय ने यू.आई.डी.एस.एम.टी.के अंतर्गत विस्तृत परियोजना (डी०पी०आर०) रिपोर्ट को शीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री डी०सी०मिश्रा, सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश तथा श्री ए०के०श्रीवास्तव, सचिव, आवास एवं नगर नियोजन ने किये जा रहे सुधार कार्यों के बारे में जानकारी दी।

अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रो०निशीथ राय, निदेशक, रीजनल सेंटर फार अर्बन एण्ड इन्वायरनमेंटल स्टडीज, लखनऊ ने जिलाधिकारियों हेतु कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशालाओं का समन्वयन डा०यू०बी०सिंह, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया।

## ➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम

### **अर्बन लोकल बॉडीज : न्यू पर्सपेक्टिव**

स्थान : लखनऊ

तिथि : 22 से 24 फरवरी, 2006

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा एक त्रि-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्बन लोकल बॉडीज : न्यू पर्सपेक्टिव' दिनांक फरवरी, 22 से 24 2006 को आयोजित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को अद्यतन

Studies organised a 3-days training programme on Urban Local Bodies : New Perspective from February 22 to 24, 2006 at Lucknow.

The main objectives of the training programme were to acquaint the participants with the roles and responsibilities of elected representatives vis-a-vis municipal officials in the context of 74th CAA, measures for achieving the goal of good urban governance, and role of Central and State Finance Commissions and to familiarise them with the recent policy decisions of the Government of India.

There was a Panel Discussion Session on the last day on "Problems and Suggestions in Strengthening Municipal Resources", which was presided over by Sri S.P. Singh, Special Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Urban Development Department, who also distributed the certificates to the participating officers.

The programme was attended by 16 Executive Officers from different Nagar Panchayats of the State of Uttar Pradesh.

Besides the internal faculty of the RCUES, headed by Prof. Nishith Rai, Director, the guest faculty consisted of various experts in the field of urban government and financial administration, namely, Sri A.K. Gupta, Chief Engineer, Directorate of Local Bodies, Government of U.P.; Sri S.B. Verma, Chief Finance and Accounts Officer, Non-Conventional Energy Development Agency (NEDA), Government of U.P. and Dr. B.C. Goel, Consultant, IIIrd State Finance Commission, U.P.

The evaluation of the course by the participants, some of them being newly appointed, revealed that they had benefited to a great extent from the various talks given to them.

The course was directed by Dr. Richa Varmani, Joint Director.

### **Sponsored Programme**

#### **➤ Training, Programme**

#### **'Womens' Entrepreneurship Development Programme' (EDP)**

Venue : Lucknow

Date : January 28, to March 9, 2006

Young women, who have completed their studies and who have a background of science and technology, were trained in the art and science of entrepreneurship so that they could become self-sufficient as well as generate jobs for others. Thus a six weeks' training programme was organized for women with science and technology background.

The main objective of the training programme was to help the participants to identify their strengths as women entrepreneurs, so that they could select their

प्रशासनिक एवं सम्बन्धित वित्तीय पहलुओं से और शासन की नई नीतियों की जानकारी देना था। कार्यक्रम में प्रमुखतः नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं म्युनिसिपल अधिकारियों को 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना था। नगरीय सुशासन को प्राप्त करने के उपाय, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की भूमिका एवं भारत सरकार द्वारा लिए गये नये नीति निर्णयों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान एक पैनल परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय 'निकाय स्रोतों को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव एवं उपाय' था। पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता श्री एस0पी0सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई, जिन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के नगर पंचायतों के 16 अधिशासी अधिकारियों ने प्रतिभागिता की।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र के आंतरिक फैकल्टी के अतिरिक्त नगरीय प्रशासन एवं वित्तीय प्रशासन के भी विशेषज्ञों ने वक्तव्य दिये, जिनमें श्री ए0के0गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश; श्री एस0बी0वर्मा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नेडा, उत्तर प्रदेश तथा डा0बी0सी0गोयल, सलाहकार, तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश के थे।

प्रशिक्षण के मूल्यांकन में सभी प्रतिभागियों (कुछ प्रतिभागी नव-नियुक्त थे) ने बताया कि सभी व्याख्यान उनके लिए बहुत लाभप्रद थे।

कार्यक्रम का निर्देशन डा0ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक ने किया।

### **प्रयोजित कार्यक्रम**

#### **➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम**

#### **महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम**

स्थान : लखनऊ

तिथि : जनवरी 28 से मार्च 9, 2006

युवा महिलायें, जिन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली है और जिनका विज्ञान एवं तकनीक से सम्बन्ध था, उनको उद्यमिता की कला एवं विज्ञान में प्रशिक्षित किया जाये, ताकि वे आत्म-निर्भर हो सकें तथा अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। अतः छः सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसी महिलाओं हेतु आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को महिला उद्यमियों के रूप में उनकी शक्तियों से परिचय कराना था, जिससे कि वे अपनी परियोजनाओं का चयन कर सकें।



projects and prepare their business plan, thereby upgrading their technical skills.

The participants of the course included 21 women who completed the entire course.

The programme was inaugurated by Prof. Nishith Rai, Director of the Centre while the valedictory address and certificates were given away by Sri Rajendra Chaudhary, Hon State Minister and Vice President, Council of Science and Technology. During the valedictory session, the participants also displayed their products. During his valedictory address, Sri Rajendra Chaudhary said that fashion should bring grace to women, but should not lead to gender inequality. The Vice-Chancellor, Lucknow University, Prof. R.P. Singh was also present as the guest of honour.

The programme was coordinated by Dr. Padma Iyer, Deputy Director.

### ➤ **Special Activity Under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission**

The Regional Centre has been designated by the Government of Uttar Pradesh as the **State Resource Centre** for the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) which is the largest ever initiative taken by the Government of India in the urban sector.

The two Sub-Missions envisaged under the JNNURM focus on 'Urban Infrastructure and Governance' and 'Basic Services for the Urban Poor' respectively. The Mission with a budgetary provision for of Rs. 50,000 crore for a period of seven years, shall provide grant assistance to the 63 cities initially identified for the specified activities.

The Regional Centre, Lucknow as 'State Resource Centre' has so far performed certain key activities in order to enable the identified cities to get their respective City Development Plans (CDPs) prepared.

The procurement of Consultant for each city was an important step in this direction. in order to procure suitable and expert consultants for preparation of CDPs in identified cities.

After processing the proposals received from the Consultants, technical evaluation was carried out according to the parameters identified in the Terms of Reference.

All the above mentioned major and other related miscellaneous activities were carried out by Prof. K. Sreeram, Consultant who was assisted by Dr. Urmila Bagga, Joint Director.

कुल 21 महिला प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० निशीथ राय, निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के द्वारा किया गया, जबकि समापन उद्बोधन तथा प्रमाण-पत्र का वितरण श्री राजेन्द्र चौधरी, माननीय राज्यमंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों ने अपने उत्पादों को भी दर्शाया। मा० मंत्री जी ने अपने समापन भाषण में कहा कि फैशन स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाता है, परन्तु इसे लिंग भेद (gender inequality) को अग्रसर नहीं करना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० आर० पी० सिंह जी भी सम्मानीय अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. पद्मा अय्यर, उप निदेशक, द्वारा किया गया।

### ➤ **विशेष कार्य जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन**

'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को उ०प्र० शासन द्वारा **स्टेट रिसोर्स सेन्टर** घोषित किया गया है। यह मिशन भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में अभी तक किया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

मिशन के अंतर्गत दो सब-मिशन, क्रमशः अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स एवं बेसिक सर्विसेज फार दि अर्बन पुअर हैं। परियोजना के अंतर्गत सात वर्षों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें चयनित 63 शहरों में विशेष क्रिया-कलापों के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होगा।

रीजनल सेंटर द्वारा उत्तर प्रदेश में चयनित किये गए शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान (सी०डी०पी०) तैयार किये जाने में सहयोग किया जा रहा है।

इस दिशा में प्रत्येक शहर के लिए सलाहकारों का चयन एक महत्वपूर्ण कदम है। सलाहकारों द्वारा दिये हुए प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र की मूल्यांकन समिति द्वारा किया जा रहा है और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोफेसर के० श्रीराम द्वारा, डा० उर्मिला बग्गा, संयुक्त निदेशक की सहायता से सम्पन्न किया गया।

# RCUES, LUCKNOW

## Academic Calendar (2006-07)

<b>A: Regular Programmes</b>			
<b>Sl. Course No.</b>	<b>Objectives</b>	<b>Level of Participants</b>	<b>Proposed Dates</b>
<b>1. Mobilizing Financial Resources for Municipal Governance</b>	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To emphasize on various methods for optimum utilization of existing financial resources.</li> <li>☞ to familiarize the participants with the innovative financing tools like access to capital markets, tax free municipal bonds, pooled financing, Borrowing from Commercial Banks etc.</li> <li>☞ to highlight the pre conditions for innovative infrastructure financing including the pricing of urban services, and</li> <li>☞ to highlight the need for committed political and administrative leadership.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Review of Current Financial Resources</li> <li>❖ Valuation &amp; Assessment of Municipal Revenue</li> <li>❖ Reforms in Property Tax Administration</li> <li>❖ Role of CFC &amp; SFC</li> <li>❖ Role &amp; Responsibilities of DDO's</li> <li>❖ Public-Private Partnership</li> <li>❖ Community Participation</li> <li>❖ Access to Institutional Finance</li> </ul>	Chairpersons and Executive Officers from the urban local bodies and officials from parastatal agencies	April 24-28 2006
<b>2. Urban Planning and Project Management</b>	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To examine the issue of "social planning" versus "physical planning" in urban planning systems</li> <li>☞ to focus on the various institutions and instruments available for guided development;</li> <li>☞ to familiarize the participants with the various aspects of urban planning and stages of project management; and</li> <li>☞ to underline the importance of integrated approach to urban planning and project development.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Urban Challenges</li> <li>❖ Concepts of Urban Planning and Project Management</li> <li>❖ Planning Norms and Standards for Key Urban Services, like water supply, solid waste management, roads, parks &amp; recreational activities, etc.</li> <li>❖ Urban Project Management Cycle</li> <li>❖ JNNURM and Related Projects.</li> <li>❖ Emerging Urban Management Issues like Citizen's Charter, Right to Information, Transparency etc.</li> </ul>	Executive / Asst. Engineers and Executive Officers from U L B s , D e v e l o p m e n t Authorities, Housing Board, Town and Country Planning Dept. etc.	May 16-20 2006 and June 26-30 2006



Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
3. Municipal Financial Management	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To examine the prevalent inter-governmental financial relations and to identify the areas for reform</li> <li>☞ to highlight the desired arrangements to ensure financial accountability.</li> <li>☞ to examine the needed reforms in municipal accounting and auditing systems</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Intergovernmental Financial Relations</li> <li>❖ Municipal Finance: present status and need for reform</li> <li>❖ Municipal Budgeting</li> <li>❖ Municipal Financial Responsibility</li> <li>❖ Reforms in Municipal Accounting &amp; Auditing Systems</li> <li>❖ Community Participation</li> </ul>	Executive Officers, Accounts Officers / Accountants from the urban local bodies and other parastatal agencies.	May 22-26 2006
4. Urban Reforms and Governance	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To examine the emerging role of urban administrators in the changing urban scenario;</li> <li>☞ to emphasize on the need for transparency in urban governance;</li> <li>☞ to familiarize the participants with the various tools and techniques to promote transparency and accountability in urban administration</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Emerging Role of Urban Management</li> <li>❖ Need for Transparency in Urban Management</li> <li>❖ Citizens Charter</li> <li>❖ Right to Information Act; and E-governance</li> <li>❖ Role of Civil Society in Urban Governance.</li> </ul>	Senior Administrative and Technical Officers from the Urban Local Bodies, Development Authorities, Housing Board, Jal Nigam, Town and Country Planning Deptt. etc.	May 25-29 2006
5. Orientation Programme	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To make the officials aware of their duties and responsibilities,</li> <li>☞ to familiarize them with the various legislations relating to urban management,</li> <li>☞ to acquaint them with the working of ULBs including the financial management.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Salient Features of 74<sup>th</sup> CAA</li> <li>❖ Financial Resources of ULBs and the need for their mobilization</li> <li>❖ Tax Management</li> <li>❖ Municipal Budgeting, Accounting and Auditing</li> </ul>	Newly Appointed Executive Officers	May 30 to June 03 2006

Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
6. Urban Services and E-Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Management of Urban Services</li> <li>❖ Office Management</li> <li>❖ UPA Programmes</li> <li>❖ PPP and Community Participation</li> <li>❖ Disciplinary Enquiry and Service Rules</li> </ul> <p><b>Key objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To acquaint the participants with the basics of computers and its utility in management systems</li> <li>☞ to emphasize its application to various facets of managerial tasks</li> <li>☞ to underline its importance in promoting SMART governance</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Salient Features of 74<sup>th</sup> CAA</li> <li>❖ Financial Resources of ULBs and the Need for their Mobilization</li> <li>❖ Tax Management</li> <li>❖ Management of Urban Services</li> <li>❖ Pricing of Services, User Charges &amp; Cost Recovery</li> <li>❖ Operation and Maintenance of Services</li> <li>❖ PPP and Community Participation</li> <li>❖ E-governance at City Level</li> </ul>	Senior and middle level administrative & technical personnel from ULBs and other parastatal agencies	June 13-17 2006
7. Women Empowerment in Urban Governance	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To familiarize the participants with the various provisions of municipal legislation and other related acts</li> <li>☞ to acquaint them with the municipal management processes,</li> <li>☞ to highlight their role and responsibility in municipal administration and</li> <li>☞ to acquaint them with various developments and UPA programmes</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Municipal and other Related Legislations</li> <li>❖ Functioning of Municipal Organizations</li> <li>❖ Municipal Services</li> <li>❖ Municipal Financial Management</li> <li>❖ Private Sector and Community Participation in Municipal Administration</li> <li>❖ Urban Sector Policies and Programmes</li> </ul>	Women Mayors / Councilors	June 26-30 2006
8. Participatory Planning and Implementation of UPA Programmes	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To examine the status of UPA programmes</li> <li>☞ To examine the present institutional arrangements for UPA programmes and identify the inadequacies;</li> <li>☞ To highlight approaches to</li> </ul>	Project / Asst. Project Officers from SUDA / DUDA and Executive Officers from ULBs	July 10-14 2006

Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
9. Public-Private Partnership in Municipal Governance	<p>participatory planning for UPA programmes and their implementation;</p> <p>☞ To make them aware of the recent Government initiatives in UPA sector</p> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Urban Poverty Alleviation Programmes: An Overview</li> <li>❖ Institutional Arrangement for UPA Programmes</li> <li>❖ Participatory Planning and Implementation</li> <li>❖ Participatory Monitoring and Appraisal of the Projects;</li> <li>❖ UPA Programmes: Best Practices</li> </ul> <p><b>Key Objectives:</b></p> <p>☞ To underline the need and importance of private sector participation in urban management</p> <p>☞ to acquaint the participants with various modes of private sector participation.</p> <p>☞ to make them aware of the need to develop effective regulatory mechanism to safe guard the interests of the citizens; and</p> <p>☞ to acquaint participants with best municipal- private sector participation in various sectors.</p> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Need for Private Sector Participation in Urban Management</li> <li>❖ Modes/ Options of Municipal- Private Sector Participation</li> <li>❖ Development of Regulatory Framework and Enabling Environment for Private Sector Participation.</li> <li>❖ Successful Case Studies in municipal governance participation;</li> <li>❖ Operationalisation of private sector participation like tendering, contracting, etc</li> <li>❖ E-governance</li> </ul>	Elected representatives, senior and middle level administrative & technical personnel from ULBs & parastatals	July 24-28 2006
10. Area Based Property Tax System: Principles and Practices	<p><b>Key Objectives:</b></p> <p>☞ To make the participants aware of the principles of the area based property tax system, .</p> <p>☞ to acquaint them with necessary tools and techniques for the administration of the new system</p> <p>☞ to highlight the managerial and personnel issues that need attention while switching over to the new system</p> <p>☞ Measures that need to be taken to ensure that the new system is citizen-</p>	Executive Officers, Tax Inspectors and elected representatives	August 21-25 2006



Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
11. Good Urban Governance: Principles and Practices	<p>friendly and transparent.</p> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Importance of Property Tax Administration in Present Urban context.</li> <li>❖ Salient Features of Area-Based Property Tax System</li> <li>❖ Implementing the Self-assessment System.</li> <li>❖ Changes Required for Administering the Area-Based Property Tax System, including Computerization of the Tax Management</li> <li>❖ Necessary Measures to make the system citizen- friendly</li> </ul> <p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To make the participants aware of good governance attributes</li> <li>☞ to highlight the need for SMART governance in the changing urban context</li> <li>☞ to highlight the best urban governance practices in the country and else where, and</li> <li>☞ to examine the feasibility of their replication and the consequential change that needs to be undertaken-legislative, administrative etc.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Good Governance: Concept &amp; Attributes</li> <li>❖ Municipal Structures and Organizations</li> <li>❖ Financial Management</li> <li>❖ Urban Services &amp; E-governance</li> <li>❖ Private Sector and Community Participation in Urban Management</li> <li>❖ Successful Case-Studies</li> <li>❖ Inter- Agency Coordination</li> <li>❖ Report Card System</li> </ul>	<p>Chairpersons, Senior administrative personnel and Executive Officers from Class-I ULBs and parastatal agencies</p>	<p>August 28 to September 01 2006</p>
12. Management of Urban Environment	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To make the different organizations dealing with the urban developmental activities realize the need for environmental protection</li> <li>☞ to acquaint the participants with various laws relating to urban environment and the agencies responsible for their enforcement</li> <li>☞ to highlight the adverse environmental impact, in general and on air, water and noise in particular, in the context of changing urban scenario, and</li> <li>☞ to underline the need for active civil society participation in environmental management.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Urban Environmental Policy</li> <li>❖ Urban Environmental Planning &amp;</li> </ul>	<p>Elected Representatives, Senior Administrative and Technical personnel from the Urban Local Bodies, Development Authorities and Housing Board, etc.</p>	<p>September 12-16 2006</p>

Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
13. Management of Low Cost Housing Schemes	<p>Management including Legislation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prevention and Control of Air, Water and Noise Pollution</li> <li>❖ Inter-Institutional Coordination: Issues and Prospects</li> <li>❖ Promoting Public Awareness and the Role of Civil Society in the Management of Environment</li> </ul> <p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To highlight the importance of low cost housing in the present urban scenario;</li> <li>☞ to identify available low cost housing policy options</li> <li>☞ to emphasize upon the advance planning, adoption of appropriate management techniques, low cost design and construction material etc.</li> <li>☞ to underline the importance of participatory approach to low cost housing projects, etc.,</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Housing Policy</li> <li>❖ Need and Importance of Low-cost Housing Projects</li> <li>❖ Low Cost Designs, Building Material and Construction Techniques</li> <li>❖ Financing of Low Cost Housing projects</li> <li>❖ Public-Private Partnership and Community Participation.</li> <li>❖ Energy Efficient Techniques, viz. solar passive architecture techniques in the construction of buildings and solar photovoltaic &amp; solar thermal devices / systems for buildings</li> </ul>	Executive / Asst. Engineers from the Municipal Corporations / Class-I cities / Development Authorities and Housing Board.	September 19-23 2006
14. Municipal Accounting and Auditing	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To highlight the deficiencies in the present system of municipal budgetary, accounting and auditing practices,</li> <li>☞ to underline the need for reforms in this sector and to identify the available courses of actions to bring about the desired changes,</li> <li>☞ to make the municipal financial processes transparent and accountable to all stake holders, and</li> <li>☞ To identify measures to promote transparency and accountability in financial management.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prevalent Budgetary Processes and Practices,</li> <li>❖ Present Accounting Practices and their Shortcomings</li> <li>❖ Reforms in Budgetary Practices, including the Participatory Budgeting,</li> <li>❖ Double Entry System and the actions to</li> </ul>	Senior and Middle level Accounts Personnel from ULBs and other parastatal agencies.	September 25-29 2006

Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
15. Management of Urban Water Supply Undertakings	<p>be taken to implement the same and</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Improved practices in auditing, including Social Audit</li> </ul> <p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To review the existing management practices in relation to O &amp; M of the systems, its management structures, personnel, budgeting etc. &amp; identify the deficiencies.</li> <li>☞ to underline the adoption of innovative financial mechanism for efficient management of water supply undertakings including rationalization of user charges and appropriate pricing policy</li> <li>☞ to stress upon the need for private sector and community participation in the management of water supply services.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Planning for Urban Water Supply Schemes</li> <li>❖ Financing of Urban Water Supply Sector Projects</li> <li>❖ Operation and Maintenance of Urban Water Supply Schemes</li> <li>❖ Key Issues in the Delivery of Water Supply Services</li> <li>❖ Pricing Policy, User Charges &amp; Cost Recovery</li> <li>❖ Private Sector Participation and the Need for Regulatory Mechanism</li> <li>❖ Community Participation</li> <li>❖ 24 x 7 Water Supply</li> </ul>	<p>Senior and middle level technical and administrative personnel from the Jal Nigam, Jal Sansthan, water supply undertakings of class I cities and elected representatives</p>	<p>October 09-13 2006</p>
16. Management of Solid Waste	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To focus on various management issues involved in operating this service,</li> <li>☞ to highlight various low cost technical options available for its management</li> <li>☞ to underline the importance of private sector and community participation in effective provision of this service.</li> <li>☞ to stress the need for inter-agency coordination in the management of the service.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Urbanization vis-a-vis Solid Waste Management.</li> <li>❖ Storage, Collection and Transportation of Solid Waste</li> <li>❖ Disposal of Wastes: Problems and Prospects</li> <li>❖ Sewage Treatment &amp; Disposal : Latest Techniques</li> <li>❖ Operation and Maintenance of SWM System</li> <li>❖ Hospital Waste Management</li> <li>❖ Community, Civil Society and Private Sector Participation in Solid Waste Management.</li> <li>❖ Inter Participation Agency Coordination</li> </ul>	<p>Executive Officers and Health Officers from the Urban Local Bodies</p>	<p>October 16-20 2006</p>



Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
<b>17. Poverty Reduction for Social and Economic Development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Successful Case Studies.</li> <li>❖ Recycling of Waste</li> <li>❖ Carbon Trading</li> </ul> <p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To acquaint the participants with various programmes for poverty alleviation and highlight the problem areas</li> <li>☞ to discuss the institutional responses and constraints &amp; highlight possible approaches to overcome them</li> <li>☞ to stress upon the adoption of participatory approach in planning, implementation and monitoring of the programmes, and</li> <li>☞ to discuss the need for enlisting the cooperation of non governmental and community based organizations.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dimensions and Issues in Urban Poverty.</li> <li>❖ Various Programmes launched to alleviate urban poverty</li> <li>❖ Institutional Arrangements for Planning and Implementation of the Programmes.</li> <li>❖ Micro Financing for Urban Poverty Alleviation programmes</li> <li>❖ Inter Agency Coordination in the Management of UPA Programmes,</li> <li>❖ Role of Civil Society in the Management of urban poverty alleviation programmes and</li> <li>❖ Transparency in the management of urban poverty programmes.</li> </ul>	<p>Project / Asst. Project officers from SUDA / DUDA and Executive Officers from ULBs</p>	<p>November 06-10 2006</p>
<b>18. Master Plan and Zoning Regulations</b>	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ To highlight the importance of appropriate city planning in shaping and guiding the physical growth and development of towns in harmony with their social and economic needs.</li> <li>❖ To emphasise upon the implementation of building bye-laws and zoning regulations in improving the environment of city and</li> <li>❖ To highlight the importance and techniques of rain water harvesting</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Master Plans and Zoning Regulations</li> <li>❖ Building Bye- Laws relating to resistance to earth quakes, other natural hazards &amp; protection against fire hazards,</li> <li>❖ Importance and Techniques of Rain Water Harvesting</li> <li>❖ Bye Laws relating to Basic Amenities, including adequate parking and open spaces.</li> <li>❖ Management and Legal Aspects relating to Enforcement of the Bye-Laws.</li> <li>❖ Inter-Agency Coordination</li> </ul>	<p>Town Planners, Technical and Administrative Personnel from Development Authorities, Housing Board and ULBs etc.</p>	<p>November 20-24 2006</p>

Sl. Course No.	Objectives	Level of Participants	Proposed Dates
19. Municipal Office Management	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To discuss the need and importance of office management,</li> <li>☞ to emphasize upon the automation of office procedures.</li> <li>☞ to highlight the importance of computerization of organizational operations.</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Organization and Methods Techniques</li> <li>❖ Office Records Maintenance of Inventory Management</li> <li>❖ Application of Computers in Municipal Organizations</li> <li>❖ Office Layout and Space Management.</li> <li>❖ E-governance</li> </ul>	Senior administrative personnel from the ULBs and parastatal agencies.	December 11-15 2006
20. Departmental Enquiry and Other Service Matters	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To sensitize the officials with the criteria &amp; procedure relating to departmental enquires and to highlight the role of administration to familiarize them with the rules relating to punishments, their imposition, conduct of enquiry and enquiry report etc.,</li> <li>☞ to discuss about the legal aspects of departmental enquiries as well as other service matters</li> </ul> <p><b>Focus Areas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Departmental Enquiries and Principles of Natural Justice</li> <li>❖ Code of Conduct</li> <li>❖ Punishments &amp; Their Impact</li> <li>❖ Procedure for Imposition of Punishments</li> <li>❖ Role and Responsibilities of Enquiry Officers</li> <li>❖ Suspension</li> <li>❖ Enquiry Report, Appeal and Review</li> <li>❖ Confidential Report and Adverse Entry</li> </ul>	Senior administrative and technical personnel from ULBs and other parastatals	January 08-12 2007
21. Report Card System	<p><b>Key Objectives:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ To acquaint the participants with the necessity and importance of Report Card System</li> <li>☞ to familiarize them with the process, system of survey and benefits from Report Card System</li> </ul> <p><b>Focus Areas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Need, Importance &amp; Concept of Report Card System</li> <li>❖ Sampling Strategy &amp; Questionnaire Design and Data Analysis for Report Card</li> <li>❖ Preparation of Report Card</li> <li>❖ Report Card System: Initiatives and Experience</li> </ul>	Senior and middle level personnel from Class I ULBs and parastatal agencies	February 07-09 2007

**B: Specialised Computer Orientation Programmes**

**Target group: Executive Officers, Accountants and Technical Personnel from urban local bodies and parastatal agencies.**

Programme I :	August	07-12, 2006
Programme II :	October	09-14, 2006
Programme III :	November	13-18, 2006
Programme IV :	December	18-23, 2006
Programme V :	January	16-21, 2007
Programme VI :	February	13-18, 2008

**C: Sponsored Training Programmes**

☞ **For Women Councilors**

☞ **Capacity Development Programmes under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission : for seven identified cities of U.P.**

**Target group**

- ❖ Senior officials dealing with planning and management of the Mission Programmes at the State level
- ❖ Middle level officials of the departments/ agencies at the State level
- ❖ Senior officials at the divisional and district levels
- ❖ Senior/middle level personnel at the city level
- ❖ Specialised courses for the personnel dealing with budgeting, accounting and auditing
- ❖ Elected representatives, representatives of civil society, neighbourhood committees/community development societies of selected cities

☞ **Capacity Development Programmes under**

**Urban Infrastructure Development Scheme For Small And Medium Towns (UIDSSMT) & Integrated Housing and Slum Development Programmes (IHSDP)**

**Target group**

- ❖ Senior officials at the divisional and district levels
- ❖ Senior/middle level personnel at the city level
- ❖ Specialised courses for the personnel dealing with budgeting, accounting auditing
- ❖ Elected representatives, representatives of civil society, neighbourhood committees/community development societies from cities/towns other than JNNURM cities

**D: Workshops**

- ❖ National Street Vendor Policy : July 05-06, 2006
- ❖ Role and Responsibilities of Ward Committees and Metropolitan Planning Committees : August 03-04, 2006
- ❖ Municipal Governance Appraisal : Report Card System : October 27-28, 2006
- ❖ Carbon Trading : November 15-16, 2006
- ❖ Urban Planning in New Perspective : December 21-22, 2006
- ❖ Urban Management (For District and Divisional Level Officials) : January 17-18, 2007
- ❖ Birth and Death Registration : February 15, 2007
- ❖ Rain Water Harvesting : February. 27-28, 2007

**E: Seminar**

- ❖ E-Governance : Challenges and Prospects : November 14-15, 2006

**F: Research Studies**

- ❖ Hospital Waste Management in Patna Urban Area
- ❖ A Study on Hospital Waste Management in Bhopal, Bhubaneshwar & Lucknow
- ❖ Empowerment of Women in Urban India: A Study in Select Municipal Corporations
- ❖ Administration of Property Tax : A Study of Select Municipal Corporations
- ❖ Management of Urban Water Supply Undertakings in Select Municipal Corporations
- ❖ Public-Private Partnership in Solid Waste Management : A Case Study of Lucknow
- ❖ Urban Environment Infrastructural Services in India: A Study of Public-Private Partnership Initiative
- ❖ Role Conflict among Women Representatives in Rural Local Government : A Case Study of Uttar Pradesh
- ❖ Implementation of 74th CAA: A Case Study of U.P.
- ❖ Introduction of Double Entry Accounting System in U.P.

**G: Post Graduate Diploma in Urban Management**

- ❖ It shall commence from the year 2007-08

**H: Publications**

- ❖ Urban Panorama (bi-annual publication)
- ❖ RCUES Newsletter (quarterly)



## FACULTY NEWS

### » Dr.Richa Varmani, Joint Director

- Attended Partner City Conclave for "Redefining Municipal Finance" under the European Union Project, organized by the Indian Chartered Accountant Institute at New Delhi on January 20, 2006.
- Prepared Presentation on "Local Self Government in India: Financial Administration and Resource Mobilisation" which was appreciated by the Ugandan Delegation on its visit to Agra in January, 2006.

### » Dr.Anjuli Mishra, Deputy Director

- Invited as Guest Faculty to Administrative Training Institute (ATI), Government of Jharkhand, Ranchi in the training programme on "Municipal Administration" (February 6 to 17, 2006). Delivered lectures on
  - Impact Analysis of 74<sup>th</sup> CAA
  - Salient Features of JNNURM
  - City Planning for the Urban Poor
  - Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana.

### » Dr.Rajeev Narayan, Deputy Director

- Attended the 2<sup>nd</sup> International Conference on "Intelligent Green, and Energy Efficient Buildings and Technologies and Product Expo" at Beijing, China from March 28 till 30, 2006.
- Visited Shanghai to see the Green and Intelligent Buildings and their System on 31<sup>st</sup> March and 1<sup>st</sup> April, 2006.

### » Dr.Padma Iyer, Deputy Director

- Elected as Chairperson, Alumni Association, Indian Society for Training & Development, a national level body, for the year 2006-07.

## फैकल्टी समाचार

### » डा0 ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक

- यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तत्वावधान में इण्डियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 'रि-डिफाइनिंग म्युनिसिपल फाइनेंस' पर पार्टनर सिटी कन्क्लेव में नई दिल्ली में जनवरी 20, 2006 को भाग लिया।
- लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया: फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेशन तथा रिसोर्स मोबिलाइजेशन विषय पर प्रस्तुतीकरण तैयार किया, जिसको यूगान्डा के प्रतिनिधि मंडल ने अपने आगरा के दौरे में प्रशंसा की।

### » डा0 अंजुली मिश्रा, उप निदेशक

- झारखंड सरकार के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची द्वारा आयोजित 'म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन' विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक, फरवरी 6 से 17, 2006) में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया तथा निम्नलिखित विषयों पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये
  - 74वें संविधान संशोधन का प्रभावी विश्लेषण
  - जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के महत्वपूर्ण तथ्य
  - शहरी निर्धनों हेतु नगर नियोजन
  - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

### » डा0 राजीव नारायण, उप निदेशक

- "इंटेलीजेंट ग्रीन एण्ड इनर्जी इफीसियेंट बिल्डिंग्स एवं टेक्नोलॉजी तथा प्रोडक्ट एक्सपो" पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बीजिंग, चीन में मार्च 28 से 30, 2006 को भाग लिया।
- ग्रीन एवं इंटेलीजेंट बिल्डिंगों तथा उनके सिस्टम को देखने मार्च 31 तथा अप्रैल 1, 2006 को शंघाई का दौरा किया।

### » डा0 पद्मा अय्यर, उप निदेशक

- इण्डियन सोसायटी फार ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय स्तर के संगठन की एल्युमनी एसोशिएशन की वर्ष 2006-07 के लिए चेयरपर्सन निर्वाचित हुई।

### Quotable Quotes

- 'A man without patience is a lamp without oil' - Andres Segovia
- 'Arise, awake and stop not till the goal is reached' - Swami Vivekanand
- 'Nothing in life is to be feared. It is only to be understood' - Marie Curie

# छपते-छपते

संख्या :- 990/9-5-2006 137वा/2006

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
उत्तर प्रदेश शासन।

म.न. राजस्व अनुभाग - 5

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2006

**विषय :** भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे०एन०एम०यू०आर०एम० योजना व यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० योजना तथा आई०एच०एस०डी०पी० योजनाओं के संबंध में डी०पी० आर० बनाये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या-वी०अ सं०-56/3-5-2006-5 स/05 दिनांक 2 सितम्बर, 2005 को कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु उ०प्र० जल निगम को तकनीकी नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है, जो आवश्यकतानुसार निजी संस्थाओं की सेवायें भी ले सकते हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नगरीय निकाय उक्त योजनाओं के संबंध में डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/सेतु निगम तथा निजी संस्थायें जिन्हें संबंधित निकाय उचित एवं सक्षम समझें, उनसे डी०पी०आर० निर्माण करा सकते हैं। डी०पी०आर० का निर्माण स्वयं कराये जाने हेतु नगरीय निकायों को अधिकृत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्यात से संबंधित नगरीय निकायों को अवगत कराते हुए प्रस्ताव प्राप्त कर शासन को संस्तुति त्वरित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

श्री प्रकाश सिंह  
विशेष सचिव

## Quotable Quotes

- 'Only few men think, but all have opinions'
- 'Knowledge leads to unity, ignorance to diversity'
- 'Patience is bitter, but its fruit is sweet'

- Bishop Berkeley  
- Sri Ramakrishna  
- Rousseau

## PHOTO FEATURE



### REGIONAL CENTRE FOR URBAN AND ENVIRONMENTAL STUDIES, LUCKNOW

Training Programme

*"Planning for Healthy City"* Jan.23-25,2006



Sri S.A.T Rizvi, Chairman Illrd SFC, U.P.; Sri S.P. Singh, Spl. Secy. Urban Dev., U.P.,  
Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Faculty Members with Participants.



### REGIONAL CENTRE FOR URBAN AND ENVIRONMENTAL STUDIES, LU

Training Programme

*"Workshop on Solid Waste Management & Report Card System"*



Chief Guest Sri S.P. Singh, Special Secy. Urban Dev., U.P.,  
Prof. Nishith Rai, Director RCUES and Faculty Members with Participants.



## PHOTO FEATURE



### REGIONAL CENTRE FOR URBAN AND ENVIRONMENTAL STUDIES LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW

TRAINING PROGRAMME FOR EXECUTIVE OFFICERS OF NAGAR PANCHAYATS

*"Urban Local Bodies: New Perspectives"*

Feb. 22-24, 2006



Chief Guest Sri S.P. Singh, Special Secy. Urban Dev., U.P.,  
Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Faculty Members with Participants.



क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ

महिलाओं हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम

दिनांक 20 जनवरी 2006 से 9 मार्च 2006 (छ. सप्ताह)

प्रायोजक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र.

सक्रिय सहयोग: राजकीय महिला पार्लियामेंट, लखनऊ



Sri Rajendra Chaudhary, Hon State Minister Science & Technology, U.P.; Prof. Nishith Rai, Director  
RCUES and Faculty Members with Participants

## PHOTO FEATURE



Prof. Nishith Rai, Director, RCUES welcoming Sri Mohd. Azam Khan, Hon. Urban Dev. Minister, U.P.; during the inauguration of a Workshop.



Sri S.A.T. Rizvi, Chairman, Illrd S.F.C., U.P.; Sri S.P. Singh, Spl. Secy. Urban Dev. U.P. and Prof. Nishith Rai, Director, RCUES in a panel discussion.



Sri Mohd. Azam Khan, Hon Minister, Urban Dev. U.P., Sri R. Ramani, (IAS) and other distinguished guests



Sri Rajendra Choudhary, Hon. State Minister, Science & Technology, U.P. with Prof. Nishith Rai, Director, RCUES.



Prof. R.P. Singh, Vice-Chancellor, Lucknow University and Prof. Nishith Rai, Director, RCUES.



Chief Guest, Sri S.P. Singh, Spl. Secy., Urban Dev. U.P. distributing Certificates to participants



## **OUR IMPORTANT PUBLICATIONS**

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 1.  | Deliberative & Executive Wings in Local Government<br>- Das, R.B. & Singh, D.P.                                  | 1968 |
| 2.  | Training in Municipal Administration   | 1968 |
| 3.  | Towns of U.P., M.P., & Bihar<br>- Singh, D.P.  | 1969 |
| 4.  | Urban Planning & Local Authorities<br>- Das, R.B.  | 1970 |
| 5.  | Coalition Government<br>- Verma, M.S   | 1971 |
| 6.  | Urban Water Supply in U.P., M.P. and Bihar<br>- Das, R.B.  | 1972 |
| 7.  | Utility Services in a Metropolis<br>- Das R.B. & Singh, D.P.   | 1974 |
| 8.  | Property Taxes in Lucknow  | 1975 |
| 9.  | Municipal Taxation   | 1976 |
| 10. | Ghaziabad  | 1978 |
| 11. | Committee System in English Local Government<br>- Sreeram, K.  | 1979 |
| 12. | Urban Conservation & Environment<br>- Seth, J.L. (ed)  | 1988 |
| 13. | Situation Analysis of Urban Child in Uttar Pradesh<br>- Seth, J. L. & Varmani, Richa                             | 1988 |
| 14. | Urban Land Ceiling Act, U.P.<br>- Bagga, Urmila  | 1989 |
| 15. | Privatisation of Municipal Services<br>- Singh, U.B. (ed.)   | 2001 |
| 16. | Assessing Training Needs in Urban Administration<br>- Singh, U.B.  | 2003 |
| 17. | Urban Administration in India (Experiences of Fifty Years)<br>- Singh, U.B. (ed.)                                | 2004 |
| 18. | Capacity Development for Urban Governance<br>- Dwivedi, S.K. & Narayan, Rajeev                                   | 2004 |
| 19. | Empowerment of Women in Urban Administration (Experiences & Strategies)<br>- Singh, U.B. (ed.)                   | 2006 |
| 20. | Urban Management<br>- Rai, Nishith & Bagga, Urmila (ed)  | 2006 |
| 21. | Comparison of Cantonment Board and Nagar Nigam :<br>A Case Study of Lucknow<br>- Varmani, Richa & Mishra, Anjali | 2006 |

